महिला कॉलेज में शोषण : खुलासों के बावजूद शतुरमुर्ग बनी रही खट्टर सरकार

बीते कुछ दिनों से सेक्टर 16 फरीदाबाद स्थित महिला कालेज चर्चा में है। कालेज प्रशासन द्वारा छात्रओं के शोषण का ये सनसनीखेज मामला क्षेत्रीय अखबारों से निकल कर राष्ट्रीय सुर्खियों तक जा चुका है और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसके छाने की सूरत बन गई है। सरकारी विभाग और आयोग भी लीक की फकीरी में लगे हुए लगते हैं। अब तक लगभग सभी तरह के मंच रस्म अदायगी जैसा कुछ करते ही नजर आये हैं। खबर की सच्चाई और गहराई पर आधारित है मजदूर मोर्चा के लिये विवेक की ग्राउंड रिपोर्ट।

कॉलेज के सहायक प्रोफेसर वशिष्ठ, लैब असिस्टेंट जगदेव और चपरासी विक्रम पर एक छात्रा ने अरोप लगाया कि ये तीनो छात्रओं से पास कराने के बदले या अधिक नंबर देने के बदले शारीरिक संबंधों की मांग करते हैं। इस सनसनीखेज आरोप के कारण तीनो फरार हो गए और इनकी गिरफ्तारी के मांग को लेकर तथाकथित सवयंसेवी संस्थाएं सड़कों पर आ गयीं।

संस्कार फाउंडेशन की संयोजक परमिता चौधरी की अध्यक्षता में महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी से मिलने पंहुचा और बाद में डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। उसने डीसी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा। परमिता ने कहा कि चिंता का विषय है कि छात्राएं अब शिक्षा के मंदिर में भी सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी ओर विडम्बना यह है कि आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं।

इसी प्रकार एनएसयूआइ ने प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण अत्री के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। अत्री ने बताया कि वशिष्ठ ही इस गैंग का हेड था। ये धंधा हमेशा ही इम्तिहानो के समय रंग पकड़ लेता है। इसकी शुरूआत नए दाखिले होने के समय से ही होती है। जब लडकियां दाखिला लेने आती हैं तो ये घटिया लोग लड़कियों का फोन नंबर नोट कर के रख लेते हैं और बाद में उन्हें पास कराने या अधिक नंबर देने का झांसा देने के नाम पर फोन करते रहते हैं। अत्री ने बताया कि यही क्रम कई वर्षों से चल रहा है जिसको लेकर उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल नरेन्द्र को भी सूचित किया था।

अगर ये सब इतने लम्बे समय से चल रहा है तो पहले क्यों नहीं इस बात पर कोई धरना या प्रदर्शन किया। अत्री ने कहा कि कि लड़कियां अपनी शिकायत लेकर आती तो थीं पर जब हम उनसे स्टैंड लेने की बात करते थे तो वो पीछे हट जातीं। इसपर उनका पक्ष कमजोर हो जाता और पूरी संभावना होती कि एनएसयूआइ पर राजनीति करने का आरोप लग जाये।

फिलहाल कालेज की छुट्टियाँ होने के चलते ज्यादा छात्रओं से बात नहीं हो सकी पर इक्का दुक्का से पूछने पर कोई ऐसी बात निकल कर सामने नहीं आई जिसमे ये साबित हो कि आरोप सच्चे हैं या झूठे। विक्रम चपरासी के सहकर्मियों से बात करने पर माली उमाकांत ने कहा कि उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, वो तो बस तलवार से अपनी घास काटने में व्यस्त रहते थे और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। यानी पचड़े में कौन पड़े?

निविदा पर काम करने वाले एक अन्य चपरासी 26 वर्षीय दीपक ने बताया कि साहब ये मानो कि इस कालेज से गंद चला गया। ये जो वशिष्ठ था ना ये बहुत गंदा आदमी था और जगदेव भी इसी का बन्दा था। दीपक ने कहा कि अब आप ही बताओ जब एक बॉस ही गलत होगा तो उसके नीचे वाले तो और बिगड़ जाएंगे। विक्रम किस स्वभाव का व्यक्ति था पूछने पर दीपक ने बताया कि वो बहुत ही गंदा लड़का था और लड़कियों पर गन्दी नजर रखता था। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि ऐसा कई बार हो चुका है कि लडकियां रोते हुए उनसे कहती थीं कि देखिये भइया ये वशिष्ठ सर हमसे पास कराने के बदले में पैसे मांगते हैं और जगदेव और विक्रम गलत सम्बन्ध बनाने की मांग करते हैं।

कालेज में ही काम करने वाली एक अन्य महिला चपरासी से पूछा कि विक्रम पर यौन शोषण के आरोप हैं तो क्या कभी विक्रम के साथ काम करते वक्त ऐसा नहीं लगा कि वह इस किस्म की मंशा रखने वाला व्यक्ति है? इसपर उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा उन्हें कभी भी नहीं लगा बल्कि विक्रम हमेशा ही उन्हें पूरी इज्जत देते हुए आंटी जी ही कहता था। ये महिला चपरासी दीपक की पत्नी थीं। दीपक के ये बोलने पर कि सब बातें खुल के बोल दे डरने की कोई जरूरत नहीं है, महिला ने कहा कि उनके पास भी लड़कियां ऐसी शिकायत लेकर आती रहीं कि वशिष्ठ सर और जगदेव पास कराने के एवज में पैसों की मांग करते हैं। इस पर हम सिर्फ सांत्वना देकर चुप रह जाते हैं और इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते थे।

हमारे ये पूछने पर कि ये लडकियां आप के पास ही ऐसी शिकायत लेकर क्यों आती थीं, दीपक और उनकी पत्नी ने कहा कि पता नहीं क्यों, पर हो सकता है परेशान आदमी किसी से भी अपनी बात तो कह ही देता है इसलिए लड़कियों ने हमसे कह दिया हो।

कॉलेज स्टाफ इस मसले पर बोलने को राजी नहीं पर एक स्टाफ ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वशिष्ठ साहब के खिलाफ मोर्चाबंदी पिछले कई महीनो से हो रही है। पुरानी प्रिंसिपल के समय में पेड़ों की अवैध कटाई और बिक्री जैसे मामले को वशिष्ठ जी ने ही उठाया था और वही भूत उनका पीछा कर रहा है। कालेज के कई सदस्य उनसे इसी बात से खफा हैं और अब साजिशन उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने आगे बताते हुए यहाँ तक कहा कि जिस लड़की ने शिकायत दर्ज की है वो बस एक मोहरा है जबकि उसके पीछे इसी कालेज की कुछ महिला स्टॉफ हैं। इन्ही के भड़कावे से लड़की ने आरोप लगाये हैं। यहाँ तक कि उन पर भी इस साजिश को सफल बनाने के लिए झूठी गवाही देने का दबाव आया था।

कालेज के एक अन्य पुराने स्टाफ ने भी नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिस विक्रम को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो निर्दोष है। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती और वो जानते हैं कि विक्रम के उस लड़की से कुछ अधिक ही मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थे; तो ये कैसे संभव है कि विक्रम उसका शोषण कर रहा हो। अब तो ये है कि लड़की कुछ भी बोल दे तो बस वही सही है, जबकि यदि निष्पक्ष जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

छानबीन में सूत्रों से कुछ अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध हुईं जो इस पूरे मामले को एक नयी दिशा देती हैं। एक सक्रिय छात्र नेता ने बताया कि वशिष्ठ को तो बस बलि का बकरा बनाया गया है। असल झगडा तो प्रिंसिपल की कुर्सी का है जिसपर नरेन्द्र बैठा हुआ था। क्योंकि वशिष्ठ विधायक मूलचंद शर्मा का रिश्तेदार है और उसकी पकड़ ऊपर तक थी तो वही नरेन्द्र को लेकर आया था। पर इसी सीट पर तिगाँव कॉलेज वाले प्रिंसिपल इकबाल की भी नजर है। इकबाल के इशारे पर ही एनएसयूआइ का एक बड़ा छात्र नेता अनिल चेची इतना बढ़-चढ़ कर प्रदर्शन कर रहा है। अब जब इस मामले में प्रिंसिपल चलता हो गया है तो इकबाल की नजर इस कुर्सी पर है।

कालेज के एक अन्य स्टाफ ने कालेज में होने वाले हर गलत काम का ठीकरा तीनों आरोपियों के सर मढ़ते हुए कहा कि यही थे जो पूरे कालेज की अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। जबकि बेचारे प्रिंसिपल साहब तो नाहक ही फंस गए। निविदा कर्मचारियों की तनख्वाह न देना जैसे काम भी यही वशिष्ठ करता था। हमारे ये पूछने पर कि ऐसा कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति इतनी अव्यवस्था फैला दे और कोई कुछ न कर सके तो कर्मचारी का जवाब था कि उसकी पहुँच मंत्रियों तक है और आप खुद देख लो इतने दिन हो गए हैं पर अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है तो इसका क्या कारण है? क्या सच में पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है।

पर वहीं कालेज के पुराने स्टाफ में से एक और ने भी नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि वशिष्ठ को फंसाया गया है। लड़की ने शिकायत 28 अप्रैल को की। जब जांच कमेटी बैठी थी तब तक ये बात बाहर नहीं गई थी। पर जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही धीरे-धीरे ये बात भी सोशल मीडिया में आ गई और जो रिपोर्ट कमेटी ने 16 मई को पेश की उसकी सारी जानकारी पहले ही बाहर आ चुकी थी। इसका मतलब कमेटी के फैसले को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया और जिसमें साजिशकर्ता सफल भी हुए। जबकि छात्रा की शुरुआती शिकायत में प्रोफेसर वशिष्ठ का नाम नहीं था।

मजदूर मोर्चा के पिछले अंक में भी इस केस में विस्तार से कुछ बिन्दुओं पर चर्चा की गयी है, जिसमे छात्रा के आरोपों पर कुछ संशयपूर्ण सवाल भी उठाये गए हैं। जैसे कि साइंस की छात्रा को वशिष्ठ जैसा कॉमर्स का प्रोफेसर कैसे ट्यूशन पढ़ाने को कह सकता है और शिकायतकर्ता ने वशिष्ठ का नाम शुरू से क्यों नहीं डाला।

इस बीच पंजाब केसरी ने एक ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो की बातचीत में एक व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से लड़की को किसी होटल में आने की बाबत बार-बार दबाव बना रहा है और लड़की ये जानना चाह रही है कि यदि वो मना कर दे तो क्या नफा नुकसान है? विडियो पीड़ित लड़की और जगदेव के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग बतायी गई है। जबकि पंजाब केसरी के यू-टयूब चैनल पर इस बातचीत को छात्रा और प्रोफेसर वशिष्ठ के बीच हुई बताया गया है। एक और रिकॉर्डिंग कालेज के एक स्टाफ ने अपने पास होने का दावा मजदूर मोर्चा से किया है जिसमे उन्हें प्रोफेसर वशिष्ठ को फंसाने के लिए कहा जा रहा है, फर्जी बयान देकर। हालांकि अब तक ऐसी कोई विडियो या ऑडियो मजदूर मोर्चा के पास नहीं पहुंची है।

हर तरफ से बातें निकल कर आ रही है। पूरे मामले में गुटबाजियां साफ तौर पर दिख भी रही हैं। छात्रों से अलग ट्यूशन पढ़ाने के पैसे लेना और अधिक नंबर देना जैसी खबरें हमारे समाज में आम हो चली हैं पर नंबर देने के बदले शारीरिक संबंधों की मांग एक भयावह घटना है।

इतने गंभीर आरोपों को महज एक कॉलेज या कुछ कॉलेज-स्टाफ तक सीमित मान कर चल रही खट्टर सरकार पर भी लानत भेजनी चाहिए। सिर्फ पुलिस केस से कुछ खास बदलने वाला नहीं है। जरूरत है कि एक व्यापक जांच आयोग राज्य के तमाम कॉलेज और विशेषकर महिला कॉलेज के ढाँचे का जायजा ले और पारदर्शी तरीके से इसे सही करने की दिशा में कदम उठाये जायें। अन्यथा अगले स्कैंडल की प्रतीक्षा करें।

रैबीज़ वेक्सीन की जगह केवल राष्ट्रवाद के टीके उपलब्ध हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा सरकार के बीके जैसे तमाम अस्पतालों में तो रैबीज़ (कुत्ता काटे) के इंजेक्शन हैं ही नहीं बल्कि राज्य भर के तमाम ईएसआईसी के अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में भी ये टीके अगस्त 2018 से उपलब्ध नहीं हैं। विदित है कि हरियाणा भर के तीस लाख से अधिक मज़दूर ईएसआईसी कवर्ड हैं। इसके लिये प्रत्येक मज़दूर से, उसके वेतन का साढे छः प्रतिशत मासिक वसूला जाता है; यह कह कर कि ईएसआई कार्पोरेशन उसको व उसके परिवार को तमाम तरह की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायेगी।

इस योजना के अनुसार ईएसआई कार्पोरेशन राज्य के मज़दूरों से प्रति वर्ष 3000 करोड़ से अधिक झपट लेती है। चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिये ईएसआई निगम ने यह काम हरियाणा सरकार को सौंप रखा है। राज्य सरकार ने इस काम के लिये बाकायदा ईएसआई हेल्थकेयर निदेशालय, पंचकुला में बना रखा है जिसमें एक निदेशक व सौ से अधिक कर्मचारी मज़दूरों के पैसे पर मौज मारते हैं। गौरतलब है कि ईएसआई निगम की ओर से राज्य सरकार से खुली छूट है कि वह ईएसआई नियमावली के अनुसार हर तरह का स्टाफ़ भर्ती करे व हर तरह के उपकरण व दवायें आदि की खरीद करे जिसका पूरा पैसा ईएसआई निगम अदा करेगा। गत वर्ष तक निगम कुल खर्च का आठ बटा सात यानी 8 रुपये खर्च में से सात रुपये देता था। शेष आठवां भाग यानी एक रुपया राज्य सरकार को वहन करना होता था।

राज्य भर के तीस लाख ईएसआई कवर्ड मज़दूरों को देखते हुए राज्य सरकार को कम से कम 1200 करोड़ का बजट बनाना चाहिये जबकि यह निकम्मी सरकार बजट बनाती है केवल 162 करोड़ का। जाहिर है इतने कम बजट में न तो डॉक्टर व यन्य स्टाफ़ भर्ती किये जा सकते हैं और न ही पर्याप्त उपकरण व दवायें खरीदी जा सकती है। सरकार की इस हरामखोरी के चलते अपने वेतन से साढे छः प्रतिशत मासिक कटाने वाला मज़दूर बीमार होने पर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। ईएसआई में इलाज न मिलने पर वह नीम-हकीमों के चक्कर में पड़ कर अपना जीवन दांव पर लगाने को मजबूर होता है।

'मज़दूर मोर्चा' के 21-27 अपैल अंक में रैबीज़ वेक्सीन की उपलब्धता न होने को लेकर समाचार प्रकाशित किया गया था। उस वक्त ईएसआई हैल्थ केयर के निदेशक डॉ. अनिल मलिक से इस संवाददाता ने इस बाबत पूछा था तो उन्होंने बताया कि अभी एक-दो माह पहले ही उन्हें रैबीज़ वेक्सीन की कमी का पता चला है। और वे शीघ्र इस कमी को पूरा करायेंगे। अगस्त 2018 से अब मई 2019 समाप्त होने जा रहा है लेकिन डॉ. मलिक की शीघ्रता कितनी लम्बी होगी कोई नहीं जानता। इस बाबत 23 मई को पुन: उनसे फ़ोन पर बात की तो उनका जवाब पहले की तरह ही था कि उन्होंने अपने तमाम अस्पतालों को स्थानीय खरीद करने के आदेश दिये हैं जिसके लिये उनके पास असीमित वित्तीय अधिकार है। उधर स्थानीय डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास तो केवल 2000 रुपये तक की पावर है। डॉ. मलिक इसे ग़लत बताते हुये उनकी वित्तीय पावर को असीमित बताते हैं। लेकिन मज़दूरों को तो अगस्त 2018 से ये टीके नहीं मिल रहे, इसके लिये कौन जिम्मेवार है? उन्होंने तुरन्त फ़रीदाबाद के अधिकारियों से फ़ोन मिलाकर बात करने की कही।

उधर, स्थानीय स्तर पर फ़रीदाबाद की सीएमओ (ईएसआई) डॉ. चन्द्रिका मलिक से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे अभी मार्च 2018 में ही इस पद पर आई हैं और वे इस मामले को गंभीरता से देखेंगी। पूछने पर इनहोंने बताया कि डिस्पेंसरी में मौजूद डॉक्टर (इन्चार्ज) को 50000 रुपये तक की दवा प्रति दिन खरीदने की पावर है। लेकिन वे इस बाबत कुछ स्पष्टता से नहीं बता पा रही थीं। वे इसके लिये हरियाणा सरकार के कुछ नियमों की बात भी कर रही थीं जिनके बारे में उन्हें अभी स्पष्टीकरण लेने की आवश्यकता है।

बहरहाल जब स्पष्टीकरण आयेगा तब आयेगा तब तक वेतन से ईएसआई का पैसा कटा कर भी मज़दूर इधर-उधर भटकने को मजबूर है। लगता है सरकार की नीति मज़दूरों को रैबीज़ के टीके एवं अन्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के बजाय देशभक्ति राष्ट्रवाद तथा वंदेमातरम की घुट्टी पिला कर ही बहलाने की है और ईएसआईसी कोष में पड़ा मज़दूरों का लाखों करोड़ रुपया एक दिन यकायक किसी अम्बानी या अडाणी की तिजोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जायेगा।